



भास्कर एकसक्तलूसिंव • 2035 तक 3 गुना बढ़कर ₹ 1.95 लाख करोड़ तक पहुंचेगा बाजार

पांच साल बाद हर तीसरा फर्नीचर ब्रांडेड होगा, अभी 20% हिस्सेदारी

अखर हकिकती | नई दिल्ली

देश का फर्नीचर बाजार बढ़त रहा है। ब्रांडेड फर्नीचर की डिमांड बढ़ रही है। फर्नीचर के बाजार में 2026 तक 3.3 लाख करोड़ रु. तक पहुंचेगा...

इन्फोटेक फर्नीचर उतार रहे हैं कंपनियां
इंटरनेशनल ब्रांड्स भी बाजार में उतरे
गैलेन इंटेरिअर, निरुध्मल आडिअन, पराजय फिनिशर...

- एडि केबरीएल मोटेरियल से लेकर फर्नीचर
आसान से फिट, फोर्डेड फिज्ड जइ सबने वाले
मटेरियल फर्नीचर, जेसे सडिअन-कम सेड...

लोग दूरे से हाथों से भी मंगवा रहे हैं फर्नीचर
अब लोग फर्नीचर को ऑनलाइन खरीद रहे हैं। फर्नीचर बाजार में तेजी से बढ़ाई जा रही है...

2021-22 में लोग फर्नीचर का खर्च 1.3 लाख करोड़ का था। अनुमान है कि साल 2026 तक 3.3 लाख करोड़ रु. तक पहुंचेगा...

भास्कर Analysis • आसान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का बढ़ा ट्रेंड कैशलेस हो रही इकोनॉमी, 1 साल में 27% बढ़ा कार्ड पेमेंट

विश्लेशक संकाशकुमार | नई दिल्ली

देश में कार्ड पेमेंट का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। बीते साल देश में कार्ड पेमेंट का खर्च 27% बढ़ा...

2021-22 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कार्ड के जरिये पेमेंट
आरबीआई के पेमेंट इकाई डेवलपमेंट फंड से मिली मदद
दो तिहाई पेमेंट कैशलेस कार्ड, जॉय कार्ड से

पेमेंट का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। बीते साल देश में कार्ड पेमेंट का खर्च 27% बढ़ा। आरबीआई के पेमेंट इकाई डेवलपमेंट फंड से मिली मदद...

बजट से उम्मीद डिपॉजिट के ब्याज पर टैक्स की दर कम हो

सुजाना ठाकुर | धर्मपुर, उत्तर प्रदेश

बैंकों में जमा पॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स कम होना चाहिए। इससे परिवारों की बचत में बँक डिपॉजिट की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

बैंकों में जमा पॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स कम होना चाहिए। इससे परिवारों की बचत में बँक डिपॉजिट की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

मंथन पर लगभग लगभग से लिए, रिजर्व बैंक ब्याज दरें लगातार बढ़ा रहा है। इसके चलते बैंकों की अस्थिरता बढ़ रही है। डिपॉजिट और ब्रॉड शीट प्रोग्राम में अंतर बढ़ता जा रहा है...

छोटी बचत की दरें बाहरी बैंकमार्क से जोड़े
भास्कर में उम्मीद है कि बहल हो जाएगा। भाजप और विजिलेंस टोपी की पहलू लगाएंगे। इस उम्मीद है कि बजट में बैंकों की भारतीया इन्फ्रस्ट्रक्चर और ब्रॉड बैंक में भारतीया बचत के उपाय किए जाएंगे। रिजर्व बैंक के लिए सकारा बजट में बैंक ब्याज पर टैक्स की दर कम करेगी।

अद्यतनी गुप ने इंडियनगैस रिजर्व के आरोपों को निराकार बतवाया
इसमें अद्यतनी गुप ने अमेरिकी एनर्जेटिक्स रिजर्व में इंडियनगैस रिजर्व के आरोपों को निराकार बतवाया है। गुप के मुताबिक, रिजर्व गैस का इन्फ्रस्ट्रक्चर और एनर्जेटिक रिजर्व को नुकसान पहुंचाने के उपाय में अद्यतनी गुप ने इंडियनगैस रिजर्व में नुकसान को कम करने के उपाय में 1.5 से 2% तक टूट रहा है।

कार्यालय नगरपालिका परिषद् भिण्ड, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

क्रमांक-ई-टेंडरिंग/निर्माण/2023/ 295 ई-निविदा आमंत्रण विज्ञापित भिण्ड, दिनांक: 24-01-2023

Table with columns: क्र. (Sl. No.), निविदा संख्या/का प्रस्ताव (Bid No./Proposal), कार्य का नाम (Work Name), अनुमानित लागत (Estimated Cost), प्रयोग शुक्ति (Material), निविदा प्रपत्र शुक्ति (Bid Form), ठेकेदार की शर्तें (Conditions), कार्य की अवधि (Duration)

नोट-1-तैयार पत्रों दिनांक 24.01.2023 तक 11:00 बजे से दिनांक 22.02.2023 को सत्र 17.30 बजे तक ऑनलाइन भरने की जा सकती है।
नोट-2-निविदा (Bid Submission and data) दिनांक 22.02.2023 सत्र 17:30 बजे तक ऑनलाइन भरने की जा सकती है।



वर्ल्ड प्ले-54

Word puzzle grid with letters H, O, B, B, Y, U, N, D, E, R, P, E, R, I, L, D, W, E, T, T, R, U, T, Y.

कोसवर्ड-54

Crossword puzzle grid with numbers 1-26.

Word search puzzle with a grid and a list of words to find.

ऑस्ट्रेलियन ओपन • सानिया-बोपन्ना फाइनल में, यह सानिया का आखिरी ग्रैंड स्लैम 14 की उम्र में सानिया के पहले जोड़ीदार थे बोपन्ना, अब अंतिम फाइनल भी उनके साथ

Main article about Sania Nehwal and Boopanna's performance at the Australian Open. Includes photos of the pair playing tennis.

Citroën C3 advertisement with image of the car and text: 'BOOK YOUR CITROËN C3 AT THE SAME PRICE AS 2022'.

Article about a woman's tennis performance: 'आरसीवी ने महिला आईपीएल के लिए दूसरे टेस्टों में नहीं किया निवेश'.

वैडमिंटन: साइना नेहावाल इंडोनेशिया मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

Article about Sindhu Nehwal's performance in the badminton tournament.

मण्डलम विविद्या विशेष् • हमारी जिम्मेदारी कि हम किसी की मेहनत और संघर्ष की भी सराहना करें: सचिन खेले में सफलता के साथ असफलता का भी जश्न मनाना जरूरी, खेल कभी हार न मानने वाली भावना सिखाता है

Opinion piece by Sachin Tendulkar on sports, success, and failure.

Advertisement for M.P. Power Generating Company Ltd. with details about a tender.

सूर्या 2022 के आईसीसी टी20 फॉर ऑफ द ईयर

Article about Suryakumar Yadav being named T20 Forerunner of the Year.

Advertisement for 'पश्चिम मध्य रेल' (West Central Railway).

Advertisement for 'पश्चिम मध्य रेल' (West Central Railway).

Advertisement for 'पश्चिम मध्य रेल' (West Central Railway).

Advertisement for 'पश्चिम मध्य रेल' (West Central Railway).

Advertisement for 'पश्चिम मध्य रेल' (West Central Railway).

Advertisement for 'पश्चिम मध्य रेल' (West Central Railway).

Advertisement for 'पश्चिम मध्य रेल' (West Central Railway).

Advertisement for 'पश्चिम मध्य रेल' (West Central Railway).

विम्बलडन ने बदले नियम, अब पुरुष डबल्स वेस्ट ऑफ-3 होगा

Article about Wimbledon tennis tournament rule changes.

Advertisement for 'मिचल प्रतिस' (Mital Pratish).

Advertisement for 'मिचल प्रतिस' (Mital Pratish).

Advertisement for 'मिचल प्रतिस' (Mital Pratish).

Advertisement for 'मिचल प्रतिस' (Mital Pratish).

Advertisement for 'मिचल प्रतिस' (Mital Pratish).

Advertisement for 'मिचल प्रतिस' (Mital Pratish).

Advertisement for 'मिचल प्रतिस' (Mital Pratish).

Advertisement for 'मिचल प्रतिस' (Mital Pratish).

Advertisement for 'ADDENDUM TO E-AUCTION SALE NOTICE'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'M.P. Power Generating Company Ltd.'.

Advertisement for 'कार्यालय नगर निगम, भोपाल' (Municipal Corporation Office, Bhopal).

Advertisement for 'महाराणा प्रताप भवन' (Maharana Pratap Bhawan).

Advertisement for 'AURANGABAD MUNICIPAL CORPORATION'.



शहर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच हाथ जोड़ी अभियान शुरू होगा प्रभारी जोशी पहुंचे गांधी भवन, बैठक ली; बागड़ी के समर्थन में अग्रवाल समाज ने संभाला मोर्चा



भास्कर संवाददाता | इंदौर

शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच हाथ जोड़ी अभियान शुरू होगा प्रभारी जोशी पहुंचे गांधी भवन, बैठक ली; बागड़ी के समर्थन में अग्रवाल समाज ने संभाला मोर्चा

चर्चा की। 26 जनवरी को वे इंदौर में आएंगे। इस मौके पर जोशी ने कहा कि 26 जनवरी से हाथ जोड़ी अभियान की शुरुआत भी होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कल्याणका का खानन भी होगा। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सूरदास पांडव, देविंदर सिंह यादव, अनूप शुक्ला, मुकेश यादव आदि मौजूद थे।

बागड़ी की नियुक्ति होल्ड करने पर अग्रवाल समाज ने जताई नाराजगी, कहा- प्रदेश में 68 में से एक भी पद समाज को नहीं



भास्कर संवाददाता | इंदौर

अग्रवाल समाज केटीएम संविधि ने अर्द्धशतक की शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चले नियुक्ति करने और कुछ ही घंटे बाद उनकी नियुक्ति को होल्ड कर रखने के निर्णय पर नाराजगी जताई। संविधि ने वॉलेंट नेतृत्वों से शहर कांग्रेस की बागड़ी बागड़ी को मोर्चे का आह्वान किया। संविधि अध्यक्ष राजेश बंसल, महामंत्री सुशोभ सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष कुलभुषण शर्मा, सुशोभ कुमारी, संजय कंकड़, विजय कुमार, पी.टी. अग्रवाल

बागू वाले, संतोष कुमार सहित विभिन्न अग्रवाल समूहों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदेश में 68 शहर एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उनमें से केवल बागड़ी ही अर्द्धशतक अग्रवाल समाज में नियुक्त हुए। उनकी नियुक्ति को होल्ड कर दो घंटे, यह प्रस्ताव है। दूसरी ओर देविंदर सिंह एवं शर अग्रवाल पर आत्म तस्क देकर एक ही अग्रवाल (एम. रामचंद्र अग्रवाल) जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं।

सीएम राइज योजना में लाभचार्ही कलेक्टर ने डीईओ का चार दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए

इंदौर | इंदौर में वन से सीएम राइज योजना के अंतर्गत कार्य शुरू हुए। कलेक्टर डॉ. इंदिरा राव ने सभी एग्रीकल्चर सेक्टर के अधिकारियों को सूचित किया कि वे अपने वेतन का 4 प्रतिशत काटें। यह निर्देश डीईओ को दिया गया है।

डीईओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपने वेतन का 4 प्रतिशत काटें। यह निर्देश डीईओ को दिया गया है।

दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को चुनाव से जोड़ने के लिए निर्माणाधीन कमेटी गठित

इंदौर | भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का द्वारा जारी निर्देश के तहत इंदौर जिले के निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्माणाधीन कमेटी गठित की। यह कमेटी दिव्यांग मतदाताओं व वरिष्ठ नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया में अधिकतम सहभागिता व सहोदरता को सुनिश्चित करेगी।

कांग्रेस नेता बोले- 75 साल में अध्यक्ष पद के लिए ऐसा झामा नहीं हुआ

अर्द्धशतक की शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नियुक्ति होल्ड करने पर शहर कांग्रेस के वॉलेंट नेता भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन यह जरूर कह रहे हैं कि यह पद समाज के लिए है। जिस तरह का झाम हुआ है, वह इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक समय यह, गंगाधर शर्मा

कांग्रेस अध्यक्ष थे। वे 80 से कुछ समय के लिए सम्मानजनक पद पर रह चुके हैं। उनके बाद 'वॉलेंट नेता' बन चुके हैं। उनका जन्म 1948 में हुआ था। उनका जन्म 1948 में हुआ था। उनका जन्म 1948 में हुआ था।

कांग्रेस अध्यक्ष थे। वे 80 से कुछ समय के लिए सम्मानजनक पद पर रह चुके हैं। उनके बाद 'वॉलेंट नेता' बन चुके हैं। उनका जन्म 1948 में हुआ था। उनका जन्म 1948 में हुआ था।

कांग्रेस अध्यक्ष थे। वे 80 से कुछ समय के लिए सम्मानजनक पद पर रह चुके हैं। उनके बाद 'वॉलेंट नेता' बन चुके हैं। उनका जन्म 1948 में हुआ था। उनका जन्म 1948 में हुआ था।

न्यूज ब्रीफ

कुशावला समाज प्रदेश में मांगेगा अग्र बागड़ी राजनीतिक हिस्सेदार

इंदौर | कुशावला समाज प्रदेश में बागड़ी राजनीतिक हिस्सेदार बनने की मांग करेगा। इससे पहले ही प्रदेश की कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यभार को संभालने में पूर्व केंद्रिय चर्चा समूह का भूखंड की उपस्थिति अपने समाज में दर्ज नहीं हुआ। प्रभुत्व में संयुक्त को अपने हाथों में रखने की मांग की जा रही है। इससे पहले ही प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुशावला ने कहा कि समाज 60 विधायकों और 200 असेंबली सदस्यों को प्रभाव देगा। इन विधायकों में से समाज के 20-40 हजार तक वोट हैं। इस राजनीति में बागड़ी हिस्सेदार बनने, निर्वाचन विचारधारा और संरचना के दिशा में शामिल हैं।

प्रवासी सम्मेलन, जीआईएस और विभागों में अछा काम करने वाले आज होंगे सम्मानित, मंत्री सिलावट करेंगे ध्वजारोहण

इंदौर | मंत्रालय में 26 जनवरी को प्रवासी दिवस का पर्व मनाया जाएगा। मुख्य 9 बजे आरंभ होगा। जय संघम मंत्री सुशोभ सिन्हा के समारोह में भाग लेना होगा। कलेक्टर डॉ. इंदिरा राव भी उपस्थित रहेंगे।

इंदौर | मंत्रालय में 26 जनवरी को प्रवासी दिवस का पर्व मनाया जाएगा। मुख्य 9 बजे आरंभ होगा। जय संघम मंत्री सुशोभ सिन्हा के समारोह में भाग लेना होगा। कलेक्टर डॉ. इंदिरा राव भी उपस्थित रहेंगे।



प्रवासी दिवस के अवसर पर अग्रवाल समाज की ओर से

नवाब महल प्रदेश में इस साल 2.58 लाख करोड़ रुपय का लेन देग

इंदौर | राष्ट्रीय धरोहर एवं कृषि विकास बैंक-नवाब महल में साल 2023-24 के लिए 2 लाख 58 हजार 500 करोड़ रुपय का लेन देग। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.43 अरब अधिक है। इसमें कृषि के लिए 1 लाख 80 हजार 160 करोड़, अंतरासंसाधन के लिए 65 हजार 832 करोड़ और अन्य प्रयोजनों के लिए 112 हजार 606 करोड़ रुपय का लेन देग है।

1 फरवरी से काम शुरू करेंगे सीएम के 4695 'जासूस', हर ब्लॉक में नियुक्त होंगे 15-15 युवा

इंदौर | प्रदेश में 1 फरवरी से जासूसों के नियुक्ति (यूएन) की प्रक्रिया शुरू होगी। जिले के वरिष्ठ अधिकारी 313 जासूसों के नियुक्ति के लिए 1 फरवरी से काम शुरू करेंगे। जिले के वरिष्ठ अधिकारी 313 जासूसों के नियुक्ति के लिए 1 फरवरी से काम शुरू करेंगे।

इंदौर | प्रदेश में 1 फरवरी से जासूसों के नियुक्ति (यूएन) की प्रक्रिया शुरू होगी। जिले के वरिष्ठ अधिकारी 313 जासूसों के नियुक्ति के लिए 1 फरवरी से काम शुरू करेंगे।

इंदौर | प्रदेश में 1 फरवरी से जासूसों के नियुक्ति (यूएन) की प्रक्रिया शुरू होगी। जिले के वरिष्ठ अधिकारी 313 जासूसों के नियुक्ति के लिए 1 फरवरी से काम शुरू करेंगे।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना : 398 बुजुर्गों को जगन्नाथपुरी की यात्रा कराएगा शासन

इंदौर | जिले में मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना का 6 फरवरी को शुभारंभ होगा। इस योजना में 398 बुजुर्गों को जगन्नाथपुरी की यात्रा कराएगा शासन।

2023 के चुनाव के लिए हर विस क्षेत्र से फंड जुटाएगी भाजपा

इंदौर | विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा हर विस क्षेत्र से फंड जुटाएगी।

इंदौर | विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा हर विस क्षेत्र से फंड जुटाएगी।

निर्माण कार्यों की जानकारी स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराए : भागवत

इंदौर | निर्माण कार्यों की जानकारी स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराए : भागवत

ADDENDUM TO E-AUCTION SALE NOTICE

ADDENDUM TO E-AUCTION SALE NOTICE. SALES PER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 (CODE)...

आयकर विभाग, इंदौर के वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर...

Advertisement for Central Bank of India, featuring the bank's logo and contact information.

Advertisement for 'Basant Panchmi Mahotsav/Bhजन बंध्या', featuring a colorful illustration and event details.

Advertisement for '74th Anniversary of India', featuring portraits of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Shivraj Singh Chouhan.

Advertisement for BhaskarAd.com, featuring a child's face and contact information.

Advertisement for '74th Anniversary of India', featuring a large '74' and event details.

Advertisement for '74th Anniversary of India', featuring a large '74' and event details.

Faced with protests, govt puts off plan to let PIB gag press

To Hold Talks With Stakeholders Before Implementing Curbs

Pankaj.Doyal@timesgroup.com

New Delhi: The IT ministry has decided to defer its plans that would mandate social media companies and other platforms to take down information marked 'fake or false' by the fact-check unit of the Press Information Bureau (PIB), or any other agency authorised by the central government.

The reversal comes in the wake of protests by the Editors Guild of India, the Indian Newspaper Society as well as the News Broadcasters & Digital Association, which said that the move would give sweeping powers to the PIB while resulting in censorship of the Press.

Amid the outrage, junior IT minister Rajeev Chandrasekhar on Wednesday said that the government would hold discussions with stakeholders early next month before the proposal was implemented. He also said that



The determination of fake news cannot be in the sole hands of the government and will result in censorship, the Editors Guild had said

consultations on the Digital Personal Data Protection Act was over and it was being processed for notification.

The government had last week released a modification to the draft Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, which it had previously released for public consultation. During the ongoing consultations largely on framing of rules for online gaming, the IT minis-

try had added a small note proposing that due diligence by intermediaries shall include making such efforts to not upload, publish, transmit or share information identified as fake or false by the PIB, which takes cognizance of fake information both suo motu and by way of queries sent by citizens on its portal or through e-mail and WhatsApp, and responds with correct information when the same pertains to the government.

"The determination of fake news cannot be in the sole hands of the government and will result in the censorship of the press," the Editors Guild said in a statement, voicing "deep concern" over the draft amendment to the Information Technology Rules.

"By legislating to become a judge in its own cause, the government, through a proposed amendment to a set of rules which have otherwise also caused concern, is taking a step to effectively muzzle criticism and even fair comment," INS said. It also said PIB, or an agency of the central government, is "ill-equipped" to serve as an entity that "meets the highest standards of fairness and due process" to ensure "factual accuracy of reports about government business on media sites", and that such a mechanism should be evolved by the ministry of electronics and IT in consultation with stakeholders.

Minister's son gets interim bail in Kheri murder case

New Delhi: In a relief for Ashish Mishra, son of Union minister Ajay Mishra and prime accused in the 2021 Lakhimpur Kheri violence that claimed eight lives, the Supreme Court on Wednesday granted him interim bail for eight weeks which can be further extended depending on his conduct, reports **Amit Anand Choudhary**. The court directed him to stay outside Uttar Pradesh and Delhi NCR and also surrender his passport to the trial court.

A bench of Justices Surya Kant and J.K. Maheshwari invoked suo motu constitutional powers and granted interim bail to four farmers arrested in a cross FIR filed by Ashish Mishra's associates for attacking their vehicle and lynching three BJP workers. The court granted them bail despite their pleaspending in Allahabad HC.

The SC said any attempt made by the petitioner, his family or supporters to influence or threaten the witnesses, shall lead to cancellation of the interim bail and the prosecution, SIT, informant or any family member of the victims of the crime will be at liberty to promptly inform this court of any incident of misuse of the concession of the interim bail.

To avoid repoll, HC suspends MP's conviction in murder bid

Disqualification By LS Secretariat Now Inoperative

TIMES NEWS NETWORK

Kochi: The Kerala high court on Wednesday suspended the conviction and sentence of Lakshadweep MP Mohammed Faizal PP in a case alleging attempted murder of a political opponent. This would mean the disqualification of the MP by the Lok Sabha secretariat, a day after the trial court's verdict, became inoperative.

While deciding to invoke the rare intervention of suspension of conviction, Justice Bechu Kurian Thomas said in the order that such a step is required to avoid a costly re-election and also considering the fact that the candidate so elected would only have a term of 15 months. Thus, the case is rare and involves an exceptional situation warranting suspension of conviction, the court said.

The court did not agree with the Union government's contention that disqualification takes effect immediately on conviction and that Parliament membership cannot be revived even if the court issues a stay. If an appellate court stays the conviction, disqualification will

The court said such a step was needed to avoid a costly re-election and also considering the fact that the candidate so elected would only have a term of 15 months. Justice Bechu Kurian Thomas said the case was rare and involved an exceptional situation warranting suspension of conviction

cease to operate, the HC said while citing a 2018 decision of the Supreme Court (Lok Prashari vs Election Commission of India and others).

While the MP is facing two CBI cases and a case registered by the local police, he has not been convicted and the benefit of innocence will have to be accorded to him in those antecedents, the court added.

Though purity in politics is required, application of the principles of rule of law cannot be denied, the court said while noting that appeal is a statutory right and that finality is only attached to the court's judgment.

The court was considering an application filed by Faizal and three others seeking suspension of conviction and sentence pronounced by a Kavaratti court in a 2009 case. While the sentence of all the ac-

cused was suspended, the conviction of only Faizal was suspended by the HC.

The case relates to the alleged assault on Mohammed Salih, a Congress worker and son-in-law of former Union minister PM Sayeed, on the day of the 2009 Lok Sabha election. It was alleged that the appellants, along with 33 others, formed an unlawful assembly and caused hurt to the complainant with weapons with the intent to kill him.

In Wednesday's order, the high court said it has to consider at the final hearing the facts of the case that alleges attempted murder in which the victim was conscious and had narrated the incident to the medical team. No sharp-edged weapon was recovered and the injuries, which were simple, were stated to be caused by blunt weapons by medical experts.

J&K police unit to track govt staffers aiding terrorism

Saleem.Pandit@timesgroup.com

Srinagar: Twenty positions will be created in J&K police for a terror monitoring group (TMG), a special unit to reinforce efforts to purge terrorism in the Union territory.

The TMG's mandate includes "taking action against hardcore sympathisers among government employees, including teachers, etc providing overt or covert support to such (terrorist) activities". Besides, it will look at cases tied to terrorist funding and also "identify all key persons, including leaders of organisations involved in supporting (terrorists) in any form and take concerted action against them".

The J&K administration ordered Wednesday the creation of the TMG, the third specialised unit in J&K police since August 5, 2019, when the special status of the erstwhile state was abrogated. The State Investigation Agency for cooperation with NIA and other central agencies, and the Special Investigation Units were created earlier. The latest order sanctions creating the posts of a senior SP, six deputy SPs, inspectors, head constables and a "follower". This follows an administrative council decision taken on January 22 with reference to the Union home ministry's move to create the TMG in 2019.

UNITED COLOURS OF THE REPUBLIC



Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus is illuminated in the colours of the national flag on the eve of Republic Day. In her address to the nation, President Droupadi Murmu on Wednesday said that India has succeeded as a democratic Republic because the Constitution serves as a source of unity

Oreva group admits 'some wrongs', offers damages

Compensation Won't Absolve Liability: HC

Ahmedabad: Clockmaker Ajanta, the Oreva Group contracted to maintain and operate the Morbi suspension footbridge that collapsed on October 30 last year, admitted in the Gujarat high court on Wednesday that "some wrong" happened under its watch, leading to the tragedy of 135 deaths. It offered to compensate the victims' kin for this, including taking



The Morbi suspension footbridge collapsed last year killing 135

care of the seven children orphaned in the disaster. It also promised to either em-

ploy or help them find jobs on becoming adults.

"Something happened at the Morbi municipality's end, and some wrong was committed by the company. Ultimately, unprecedented damage has been done," counsel Nirupam Nanavati told the court. Ajanta's commitments were in response to the high court's notice to the company on a suo motu PIL.

The court said that based on the available evidence and Morbi municipality's failure to explain why it allowed Ajanta to continue operating the suspension bridge, "an inference could be drawn that there was collusion between the two".

ADDENDUM TO E-AUCTION SALE NOTICE

SALE AS PER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 (CODE)

In continuation to the e-auction sale notice for sale of Sandhya Prakash Limited (under liquidation) as a going concern published on 16.12.2022 read with addendum published on 18.01.2023 in this newspaper, it is hereby informed that the e-auction/sale has been further extended to 14.02.2023. The other timelines in terms of the E-Auction Sale Notice and E-Auction Process Document also stand extended/modified accordingly. In this regard, please refer to the documents uploaded on the website of the Corporate Debtor www.sandhyaprakash.com and www.auramall.in.

Date: 25th January 2023 For Sandhya Prakash Limited (under Liquidation)

Sd/-
C.A. Devendra Jain
Liquidator
Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P00255/2017/2017-18/10484

RajCOMP Info Services Limited (RISL)

C-Block, 1st Floor, Vojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

RISL invites e-bids from the eligible bidders for the following:

NIB No./Date/Unique bid no.	Particulars	Estimated Cost/EMD	Start of sale /Last date
297/23.01.2023 RIS2223WLO800112	Construction and Maintenance of Rajiv Gandhi Knowledge Service & Innovation Hub at Jodhpur.	Rs. 156.50 Cr/ Rs. 3.13 Cr	25.01.2023 24.02.2023

Details can be seen on the websites <http://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://risl.rajasthan.gov.in> & <http://doitc.rajasthan.gov.in>. Bids are to be submitted through <http://eproc.rajasthan.gov.in>.

Raj.Samwad/C/22/13799 Technical Director (Civil & Electrical), IT&C

एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

SJVN Green Energy Limited

(A Wholly Owned Subsidiary of SJVN Limited)

CIN: U40100HP2022GOI009237

Notice Inviting Expression of Interest (EOI)

EOI No: SJVN/CC-Delhi/C&P/4363 Date: 26.01.2023

On behalf of SJVN Green Energy Limited, OFFLINE Expression of Interest (EOI) is invited from all Public Sector/Private Sector/ Foreign Banks in India for "Arranging term loan in foreign currency (except US\$) equivalent to US\$ 500 Million for SJVN Green Energy Limited (SGEL)". The EOI Document can be downloaded from the websites www.sjvn.nic.in and www.eprocure.gov.in from 26.01.2023 to 16.02.2023 till 14:00 Hrs (IST). The Proposal is to be submitted OFFLINE to the EOI Inviting Authority. The prospective bidders are requested to remain updated through above mentioned websites for any clarification or notification concerned with this EOI as no further information will be published in respect of this EOI through any other media.

Last Date & Time for submission of Proposals: 16.02.2023 till 14:00 Hrs

Date & Time of opening of Proposals: 16.02.2023 at 15:00 Hrs

Dy. General Manager (C&P)

6th Floor, Tower 1, NBCC Office Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Ph.- 011-61901906/61901953 E-mail - sjvncontractdelhi@gmail.com

ED can't probe any offence other than laundering: HC

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Delhi high court has held that the Enforcement Directorate (ED) does not have the powers to investigate any offence other than money laundering and the agency cannot assume by itself that a predicate offence has been committed.

"It becomes pertinent to observe that the ED stands empowered under the PMLA to try offences relating to money laundering. It neither stands conferred the authority nor the jurisdiction to investigate or to inquire into an offence other than that which stands comprised in Section 3 (of the PMLA)," single bench of Justice Yashwant Varma said in a judgment on Tuesday.

Mentioning apex court directions, the bench said, "The Supreme Court had pertinently observed that even if the ED in the course of its investigation and inquiry into an offence of money launder-

Defer Rana Ayyub hearing: SC to court

The Supreme Court on Wednesday asked a Ghaziabad court that had summoned journalist Rana Ayyub on January 27 in an alleged money laundering case to adjourn its hearing as it agreed to hear her plea challenging the jurisdiction of the lower court to proceed against her. As a bench of Justices Krishna Murari and V Ramasubramanian could not decide Ayyub's plea on merit due to paucity of time and posted the case for January 31, it asked the court to defer Friday's hearing and post it after March 31.

ing were to come across material which would otherwise constitute a scheduled offence, it could furnish the requisite information to the authorities otherwise authorized by law to investigate those allegations and consider whether they would constitute the commission of a predicate offence."

The court held that the primary function to investigate and try offences listed as scheduled offences in the PMLA vests in authorities constituted under those independent statutes.

"ED cannot possibly arro-

gate unto itself the power to investigate or inquire into the alleged commission of those offences. In any case, it cannot, on its own motion, proceed on the surmise that a particular set of facts evidence the commission of a scheduled offence and based on that opinion initiate action under the PMLA," the judgment said.

The court added that it would be evident from a perusal of the Schedule that it enlists offences defined and created under various statutes, which independently contemplate investigation and trial.

Now, ED arrests TMC's Gokhale

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Accusing Trinamool Congress spokesperson **Saket Gokhale** of laundering money collected through crowd-funding for creation of personal assets, the Enforcement Directorate on Wednesday arrested him under the Prevention of Money Laundering Act. He was arrested from judicial custody in Ahmedabad and a special court remanded him in ED custody till January 31.

Sources said ED has found that Gokhale invested over Rs 50 lakh which he had collected for public activism, in mutual funds and refused to divulge the actual source of another Rs 24 lakh received in cash. He claimed that Rs 23.5 lakh cash deposited in his bank accounts was "given

to him by Alankar Sawai of Congress for social media work and other consultancy", ED has alleged.

"There was no element of forgery in funds collected by Gokhale through an online platform which is used by even political parties. He is a full-time activist sustaining on donations received through crowd-funding. As soon as he joined TMC, he stopped accepting funds to prove his bona fide," PTI quoted Gokhale's lawyer as saying.

Sources said Gokhale had collected over Rs 1 crore through crowd-funding to launch a campaign against political leaders. However, he had diverted this money to creation of personal assets and spending Rs 4 lakh on liquor consumption as revealed from his financial transactions.

75% refund for flyers forcibly downgraded

New Delhi: Passengers involuntarily downgraded (made to travel in a class lower than they had paid for) will now get 75% of the cost of their tickets refunded for domestic flights and up to 75% for international flights, reports **Saurabh Sinha**. DGCA has amended the rules regarding "facilities to be provided to flyers by airlines due to denied boarding, cancellation of flights and delays in flights".

"The amendment will allow the passenger, who is downgraded involuntarily to be reimbursed as follows: For domestic sector: 75% of the cost of ticket, including taxes. For the international sector: 30% of the cost of ticket, including taxes, for flights of 1,500 km or less; 50% of the cost of ticket, including taxes, for flights between 1,500 km and 3,500 km; and 75% of the cost of ticket, including taxes, for flights more than 3,500 km," a DGCA official said.

6-year-old uses lesson picked up from cartoon film to survive building collapse

Himanshu Singh | TNN

Lucknow: Lessons learnt on earthquake safety through a popular cartoon show helped six-year-old Mustafa protect himself when the five-storey Alaya Apartments in Lucknow collapsed on Tuesday.

Mustafa, who is among 14 survivors, suffered minor injuries and is currently under treatment and is said to be out of danger.

Unfortunately, his mother Uzma Haider and grandmother Begum Haider could not be saved.

Mustafa told TOI he was watching television when the building shook suddenly.



Rescue operation underway after a five-storey building collapsed in Lucknow on Wednesday

"Earlier in the day, when light tremors were felt in the city, I was reminded about the dos and don'ts during an earthquake," he said.

"I was terrified but I recalled an episode of the cartoon show 'Doraemon' in which Nobita (the central character of the series) was taught about protecting himself during an earthquake by taking shelter in corners or under the bed. Without wasting a second, I took shelter under the bed," Mustafa recalled.

"I saw mummy running and screaming. Within no time, the entire building collapsed," he said.

Police commissioner SB Shiradkar said there were 17 people inside the building when it gave way and the rescue operation will continue till the "last person was traced".

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
5th Floor, "Metro Plaza", E-5 Arera Colony, Bittan Market, Bhopal - 462 016
Phone No. : 0755-2430154, 2463585, Fax No. : 0755-2981055
E-mail : secretary@mperc.nic.in, Website : www.mperc.in
No. MPERC/D (T)224 Bhopal, Date : 24.01.2023

PUBLIC NOTICE

M.P. Power Generating Company Limited (MPPGCL) has filed a petition for True up of Generation Tariff of Power Stations of MPPGCL for FY 2021-22, determined by the Commission vide Multi Year Tariff order dated 19.05.2021 read with corrigendum dated 09.09.2021. The subject petition has been filed under section 62 & 64 of the Electricity Act 2003 read with Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for determination of Generation Tariff) Regulations 2020 with following prayer :-

- Approve Annual Capacity (Fixed) Charges and Other charges for FY 2021-22 and permit adjustment of differential amount in six equal monthly instalments.
- To allow additional capitalization as per audited Annual Statements of Accounts for FY 2021-22 and accordingly permit additional Depreciation, RoE and Interest on Normative Loan/excess equity.
- As per Regulation 9.11 of Regulations 2020, allow interest on True Up amount, if any.

Power Station-wise breakup of Annual Capacity (Fixed) Charges claimed for true-up of the tariff determined by the Commission for FY 2021-22 after applying Normative Availability Factor is as given below :-

S. No.	Station	As per MYT Order dated 19.05.2021	As Claimed by MPPGCL on Normative Availability	True-up Amount
1.	ATPS PH-3	190.32	197.92	7.59
2.	STPS PH-2&3	415.49	408.33	(-7.15)
3.	STPS PH-4	626.98	630.47	3.49
4.	SGTPS PH-1&2	454.41	428.90	(-25.51)
5.	SGTPS PH-3	313.15	320.09	6.94
6.	SSTPP PH-1	1307.74	1302.88	(-4.86)
7.	SSTPP PH-2	1366.19	1412.97	46.78
8.	Thermal	4674.28	4701.55	27.27
9.	Gandhi Sagar	15.21	15.02	(-0.19)
10.	Pench	27.06	28.42	1.37
11.	Rajghat	14.89	11.96	(-2.94)
12.	Bargi	17.59	18.19	0.60
13.	Bansagar PH-1, 2 & 3	151.88	123.64	(-28.24)
14.	Bansagar PH-4	9.45	9.75	0.30
15.	Birsinghpur	6.06	5.62	(-0.44)
16.	Madhikheda	19.17	20.32	1.16
17.	Hydro	261.32	232.93	(-28.39)
	Total	4935.59	4934.48	(-1.12)

The Commission has admitted the petition and registered the same as **Petition No. 85 of 2022**. Persons intending to file comments/objections/suggestions may send the statement of comments/objections/suggestions with copies of documents and evidence directly to the **Secretary, M.P. Electricity Regulatory Commission, Metro Plaza, 5th Floor, E-5, Arera Colony, Bittan Market, Bhopal-462016** with a copy to the Chief Engineer (HR&A), MPPGCL, 1st Floor, Block No. 9, Shakti Bhawan, Rampur, Jabalpur-482008, so as to reach the Commission's office within 21 days from publication of this notice. Advance copies of comments/objections/suggestions could also be sent by E-mail.

Copy of main petition (English version) may be obtained by any interested person on any working day between **11:00 AM to 4:00 PM** from office of the Commission or from the O/o Chief Engineer, (HR&A), MPPGCL, Jabalpur on payment of **Rs. 200/-** in cash or by a demand draft drawn on any scheduled bank in favour of **MPERC, payable at Bhopal** or Sr. Accounts Officer (COG&HS), MPPGCL, payable at Jabalpur. Copy of the petition may also be obtained by post on additional payment of **Rs.50/-** towards postage expenses. This petition is also available on website of the Commission : www.mperc.in.

The Commission shall conduct a public hearing in the matter on **21.02.2023 at 11:00 Hrs.** The persons who have filed their representation in writing with the Commission within prescribed time limit may intimate their mobile number and e-mail ID to participate in the public hearing as per the relevant guidelines available on the Commission's website.
M.P. Madhyam/108333/2023 **SECRETARY**